

## सर्वोच्च न्यायालय ने वजिजापनदाताओं के लिये स्व-घोषणा अनिवार्य की

[स्रोत: पीआईबी](#)

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने आदेश दिया है कि सभी वजिजापनदाताओं/वजिजापन एजेंसियों को किसी भी वजिजापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले एक 'स्व-घोषणा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा।

- इसका उद्देश्य पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और ज़िम्मेदार वजिजापन प्रथाओं को सुनिश्चित करना है।
- ये नियम 18 जून, 2024 से सभी नए वजिजापनों पर लागू होंगे।
- यह केबल टेलीविज़न नेटवर्क (Cable Television Networks- CTN) नियम, 1994 के नियम 7 और भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण मानदंडों में दिये गए दिशानिर्देशों सहित सभी प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।
  - CTN के नियम 7 में प्रावधान है कि वजिजापनों को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिये तथा दर्शकों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस पहुँचाने से बचना चाहिये।
- वजिजापनदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रसारण सेवा पोर्टल (टी.वी./रेडियो वजिजापनों के हेतु) और [भारतीय प्रेस परिषद पोर्टल](#) (प्रिंटेड व डिजिटल मीडिया वजिजापनों हेतु) पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वजिजापनदाताओं को संबंधित प्रसारक, मुद्रक, प्रकाशक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड हेतु स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण उपलब्ध कराना आवश्यक होता है।

और पढ़ें: [भारत में भ्रामक वजिजापनों का वनियमन, केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों में परिवर्तन, पत्रकारिता सूत्रों का प्रकटीकरण](#)